[2019] 9 एस.सी.आर. 1060

बिहार और अन्य

बनाम

डॉ. चैत्रय कुमार सिंह और अन्य।

(सिविल अपील संख्या–5709/2019) 19 जुलाई, 2019

{डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्तिगण}

सेवा कानूनः स्थानांतरण–दो राज्यों का पुनर्गठन–बिहार राज्य और झारखंड राज्य में पूर्ववर्ती राज्य का विभाजन–प्रथम प्रतिवादी–चिकित्सा अधिकारी को प्रारम्भ में झारखंड राज्य को आवंटित किया गया–प्रतिवादी के अनुरोध पर तीन साल के बाद, दोनों राज्यों के आपसी सहमति के साथ बिहार राज्य के लिए आवंटन किया गया–हालांकि, प्रतिवादी ने झारखंड राज्य के कर्मचारी के रूप में काम करना जारी रखा जब तक कि वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर लिया–प्रतिवादी द्वारा, अपने सेवानिवृत्ति से कुछ दिनों पहले, दायर रिट याचिका में, बिहार राज्य में शामिल होने से उन्हें राहत देने के लिए झारखंड राज्य को निर्देश जारी करने की मांग की गयी–उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य को झारखंड राज्य से स्थानांतरण पर अपने कर्मचारी के रूप में पहले प्रतिवादी को स्वीकार करने के लिए आदेश जारी करने के लिए निर्देश जारी किया–डिवीजन बेंच द्वारा बरकरार रखा गया–अपील पर, कहा गयाः प्रथम प्रतिवादी ने अपने कानूनी उपचारों को पाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जब वह झारखंड राज्य के फैसले से व्यथित था कि उसे सेवा से कार्यमुक्त नहीं किया गया ताकि वह बिहार राज्य में शामिल हो सके–उसने उस स्तर पर उपलब्ध राहतों के लिए कानून के तहत अपने अधिकारों और उपचारों का पालन नहीं किया, बल्कि सात साल तक झारखंड राज्य के लिए काम करना जारी रखा और 30 अप्रैल 2017 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। 31 जुलाई 2017 को झारखण्ड सरकार का उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें कार्यमुक्त करने का आदेश, इसका कोई परिणाम नहीं है–अब झारखंड राज्य में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है, जिस राज्य को उन्हें मूल रूप से सौंपा गया था और जहां पुनः आवंटन के आदेश के बावजूद प्रतिवादी ने सात साल तक काम किया, यह निर्देश देना उचित नहीं होगा कि उसे बिहार राज्य द्वारा समाहित किया जाना चाहिए–इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने निर्देश और आदेश जारी करने में चूक की और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या. 5709/2019

एल.पी.ए. नं 197/2018 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 05.11.2018 से।

देवाशीष भरुका, रवि भरुका, सुश्री सर्वश्री, जस्टिन जॉर्ज, आदित्य सिंघल, अक्षय अमृतांशु, सलाहकार अपीलकर्ताओं के लिए।

कुमार शिवन, मनोज टंडन, सुश्री तुलिका मुखर्जी, सलाहकार, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश

1. अनुमति दी गई ।

2 यह अपील झारखंड के उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के एक फैसले से उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा झारखण्ड के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था कि बिहार राज्य, झारखण्ड राज्य से स्थानांतरण पर अपने कर्मचारी के रूप में प्रथम प्रतिवादी को स्वीकार करने के लिए आदेश जारी करे।

3. प्रथम प्रतिवादी को 26 मई 1989 को एक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जो इसके पुनर्गठन से पहले बिहार राज्य में था। 15 नवंबर 2000 को, बिहार पुनर्गठन अधिनियम के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती राज्य को बिहार राज्य और झारखंड राज्य में विभाजित किया गया। परिणामी राज्यों में से किसी को भी अपनी सेवाओं के आवंटन के लिए कर्मचारियों से विकल्प आमंत्रित किए गए थे। प्रथम प्रतिवादी ने बिहार राज्य का विकल्प चुना।

4. केंद्र सरकार ने 8 जून 2006 को कुछ दिशा–निर्देश जारी किए, जिसमें परिकल्पना की गई थी कि अंतिम आवंटन के बाद भी, कर्मचारियों को दोनों राज्यों की आपसी सहमति से अनुगामी राज्यों में से किसी एक में तैनात किया जा सकता है। 9 फरवरी 2007 को, केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य को प्रथम प्रतिवादी आवंटित किया, जिस पर कल्याण विभाग में बिहार सरकार ने 27 फरवरी 2007 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें प्रथम प्रतिवादी को झारखंड राज्य में शामिल होने के लिए कहा गया। 22 मार्च 2007 को, प्रथम प्रतिवादी झारखंड राज्य में शामिल हुआ और जिला सिमडेगा में एक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे।

5. 11 जनवरी 2010 को, प्रथम प्रतिवादी ने बिहार राज्य को अपने पुनः आवंटन के लिए एक आवेदन किया। दोनों राज्यों ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और 30 जुलाई 2010 को, प्रथम प्रतिवादी को बिहार राज्य को आवंटित किया गया था। परिणामस्वरूप, 6 सितंबर 2010 को, बिहार सरकार में गृह विभाग ने प्रतिवादी की सेवाओं को, बिहार राज्य को, आवंटित करने के औपचारिक आदेश जारी किए।

6. प्रथम प्रतिवादी की शिकायत यह है कि यद्यपि उसने 6 अक्टूबर 2010 को उसे कार्यमुक्त करने के लिए झारखंड राज्य को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन उसे राहत नहीं मिली ताकि वह बिहार राज्य में शामिल हो सके।

7. जो तथ्यात्मक स्थिति उभरकर सामने आती है वह यह है कि प्रथम प्रतिवादी ने झारखंड राज्य के एक कर्मचारी के रूप में काम करना जारी रखा, जहां उन्होंने 30 अप्रैल 2017 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की। सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले, प्रथम प्रतिवादी ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें निम्नलिखित अनुतोष चाही गईः –

> ''(क) प्रतिवादी सं 2 पर निर्देश देने के लिए कि याचिकाकर्ता को बिहार राज्य में शामिल होने के लिए तुरन्त राहत दें, मेमो नं0 स्ट्रा./झा./वीआई.–244/10–10416 दिनांकित 06.09.2010 में निहित अधिसूचनाके मध्य नजर, गृह (विशेष) विभाग द्वारा जारी, बिहार सरकार, जिसमें याचिकाकर्ता को दोनों उत्तराधिकारी राज्यों की सहमति से बिहार राज्य को आवंटित किया गया था।

ख) प्रतिवादी सं 3 को आगे निर्देशित करने के लिए गृह (विशेष) विभाग, बिहार राज्य द्वारा जारी मेमो नं0 स्ट्रा./झा./वीआई.–244/10–10416 दिनांकित 06.09.2010 में निहित अधिसूचना के आलोक में याचिकाकर्ता की बिहार राज्य में कार्यभार ग्रहण स्वीकार करने हेतु।

(ग) उत्तरदाताओं 1 व 2 को इस माननीय न्यायालय को यह समझाने का निर्देश देना कि किस शक्ति और अधिकार के तहत आवंटन के निर्णय के बावजूद याचिकाकर्ता को अभी तक बिहार राज्य में शामिल होने से राहत नहीं मिली है, बावजूद इसके कि दोनों उत्तराधिकारी राज्यों की सहमति से यचिकाकर्ता को बिहार राज्य को आवंटित करने का फैसला है।''

8. 31 जुलाई 2017 को, प्रथम प्रतिवादी के सेवानिवृत्त होने के बाद, झारखंड राज्य ने 30 अप्रैल 2017 से उन्हें राहत देने की घोषणा की। प्रथम प्रतिवादी के लिए बिहार में सेवानिवृत्ति की आयु 67 वर्ष लागू है, जबकि झारखंड राज्य में, जहां उन्होंने काम किया था, उन्होंने 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की।

9. रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी और डिवीजन बेंच द्वारा पत्र पेटेंट अपील में आदेश की पुष्टि की गई है।

10. डिवीजन बेंच के फैसले की सत्यता पर सवाल उठाते हुए, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री देवाशीष भारुका ने प्रस्तुत किया कि प्रथम प्रतिवादी के अनुरोध के अनुसरण में, बिहार राज्य को दोनों राज्यों की आपसी सहमति के साथ एक आवंटन किया गया था। हालाँकि, 6 सितंबर 2010 को बिहार राज्य को उनके आवंटन के बावजूद, प्रथम प्रतिवादी ने 2017 में सेवानिवृत्त होने तक झारखंड राज्य में काम करते रहे। अपीलकर्ता के अनुसार, बिहार राज्य में कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है जिसके खिलाफ अब प्रतिवादी को समाहित किया जा सकता है। यह भी आग्रह किया गया है कि यह केवल 2017 में था कि प्रतिवादी ने 6 सितंबर 2010 के आदेश को लागू करने के लिए रिट कार्यवाही शुरू की, जिंस समय तक वह झारखण्ड राज्य में सेवानिवृत्ति के कगार पर था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि अब झारखंड राज्य से सेवानिवृत्त होने वाले प्रथम प्रतिवादी, 6 सितंबर 2010 के आदेश के अनुसरण में अनुतोष नहीं मांग सकते हैं। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि उसे 12 अक्टूबर 2015 को सूचित किया गया था कि बिहार राज्य में शामिल होने के लिए उनका आवेदन, रिक्ति के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सका और उसके बाद भी, प्रतिवादी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया कि झारखंड राज्य ने उन्हें राहत दी ताकि उन्हें बिहार राज्य की सेवाओं में शामिल होने में सक्षम बनाया जा सके। श्री भारुका ने आग्रह किया कि यह केवल सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई समय सीमा का लाभ लेने की दृष्टि से था कि प्रथम प्रतिवादी अब झारखण्ड से सेवानिवृत्त होने के बाद बिहार राज्य में स्थानांतरित होने का प्रयास कर रहा है।

11. दूसरी ओर, श्री मनोज टंडन, पहले प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आग्रह किया कि 6 सितंबर 2010 को बिहार राज्य को उनकी सेवाओं के आवंटन के बाद, उस अधिसूचना को वापस नहीं लिया गया है। विद्वान वकील ने कहा कि पहले प्रतिवादी ने दोनों राज्यों के साथ सभी प्रयास किएः बिहार सरकार के साथ सेवा में शामिल होने की मांग करते हुए और झारखंड सरकार के साथ मांग करके कार्यमुक्त होना चाहिए। चूंकि उन्हें झारखण्ड राज्य से राहत नहीं मिली थी, यह आग्रह किया गया था कि उनके पास सेवा में बने रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि जब तक उन्हें बिहार राज्य को आवंटित करने की अधिसूचना जारी रहती है, उस पद पर बने रहने के लिए, तब तक अपीलकर्ताओं के पास,

भले ही वह झारखण्ड राज्य में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है, उसे लाभ से वंचित करने का कोई कारण नहीं था। ।

12. न्यायालय के समक्ष आने वाले तथ्यों से संकेत मिलता है कि 2000 में दोनों राज्यों के पुनर्गठन के बाद, प्रथम प्रतिवादी को शुरू में 9 फरवरी 2007 को झारखंड राज्य को आवंटित किया गया था। 2010 में, जब प्रतिवादी ने बिहार राज्य को फिर से आवंटन की मांग की, जो दोनों राज्यों की सहमति से केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के तहत स्वीकार्य था, तो उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था और वास्तव में उन्हें 06 सितम्बर 2010 को बिहार राज्य को आवंटित किया गया था। प्रथम प्रतिवादी की शिकायत स्पष्ट रूप से यह है कि झारखंड राज्य ने उसे राहत नहीं दी। हालाँकि, प्रथम प्रतिवादी ने अपने कानूनी उपचारों को पाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जब वह झारखण्ड राज्य के निर्णय से व्यथित था कि उसे सेवा से मुक्त करे ताकि वह बिहार राज्य में शामिल हो सके। प्रथम प्रतिवादी ने कानून के तहत अपने अधिकारों और उपचारों को इस तरह की राहत के लिए सहारा नहीं लिया, जैसा कि उस स्तर पर उपलब्ध होती। इसके बजाय, उन्होंने 7 वर्षों तक झारखण्ड राज्य के लिए काम करना जारी रखा और 30 अप्रैल 2017 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए। झारखंड सरकार ने 31 जुलाई 2017 को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राहत देने का आदेश दिया, जिसका कोई परिणाम नहीं है। प्रथम प्रतिवादी को यह सुनिश्चित करने के लिए कानून के तहत उसके पास उपलब्ध उपायों का पालन नहीं करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए कि झारखंड राज्य ने उसे बिहार राज्य में शामिल होने के लिए कार्यमुक्त का एक आदेश जारी किया। अब झारखंड राज्य में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद, वह राज्य जिसमें वह मूल रूप से नियुक्त था और जहां पुनः आवंटन के आदेश के बावजूद प्रतिवादी ने सात साल तक काम किया, यह स्पष्ट रूप से अनुचित होगा कि उसे बिहार राज्य द्वारा समाहित किया जाना चाहिए। इस तथ्य से बिल्कुल अलग कि बिहार राज्य ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनके पास कोई रिक्तियां नहीं हैं, प्रतिवादी ने 6 सितंबर 2010 के आदेश के तहत अपने अधिकारों को लागू करने के लिए कदम नहीं उठाए, तब भी जब बिहार राज्य ने उन्हें 12 अक्टूबर 2015 को सूचित किया कि वह उनकी सेवाओं को स्वीकार करने में असमर्थ था।

13. हमारा विचार है कि अपील में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी की ओर से अनुतोष के लिए प्रार्थना को स्वीकार करने में त्रुटि की।

14. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय व आदेश दिनांकित 5 नवंबर 2018 को रद्द करते हैं। इन परिस्थितियों में, लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं होगा।

15. लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाएगा।

निधि जैन अपील स्वीकृत।

विधिक सन्दर्भः–

1– सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या. 5709/2019

2– एल.पी.ए. नं 197/2018 झारखंड उच्च न्यायालय।